भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5495
05 अप्रैल, 2022 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) में समकालीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण

5495. श्री अशोक कुमार यादव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के संबंध में समकालीन प्रौद्योगिकी के नवीनीकरण, सतत निवेश सहित जलवायु परिवर्तन, तथा मूल्य और मांग में उतार-चढ़ाव से संरक्षण हेतु कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ख): सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है जो देश में जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापक नीतिगत ढ़ांचा है । एनएपीसीसी के अनुरूप अनुकूलन और लघुकरण दोनों पर भारत की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए हरित/निम्न कार्बन फुटप्रिंट प्रौद्योगियों के विकास सहित अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थानों/अनुसंधान संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

देश में अपनी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना के अलावा मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत अतिरिक्त उत्पादन फसलों को उत्पादक क्षेत्र से खपत केंद्रों तक बहुलता की स्थिति में पहुंचाने के लिए परिवहन और भंडारण पर होने वाले खर्च के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता के माध्यम से विकारी फलों और सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के उपाय कर रहा है ।

इसके अलावा निर्यात में लगे लोगों सहित खाद्य प्रसंस्करण निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विनियामक और नीतिगत सुधार किए हैं । इन उपायों में उत्पादन अनुमोदन व्यवस्था से घटक आधारित अनुमोदन प्रणाली में स्थानांतरण, मंत्रालयों में कैबिनेट सचिव और परियोजना विकास प्रकोष्ठों के अधीन सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) स्थापित करना; ऑनलाईन पोर्टल आदि के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन और अनुदान संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना शामिल हैं ।

*****